



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 134]

नई दिल्ली, बुधवार, अप्रैल 13, 2016/चैत्र 24, 1938

No. 134]

NEW DELHI, WEDNESDAY, APRIL 13, 2016/CHAITRA 24, 1938

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

अधिसूचना

मुम्बई, 5 अप्रैल, 2016

सं. टीएएमपी/21/2009-डब्ल्यूएस.—पोत परिवहन मंत्रालय में भारत सरकार द्वारा जारी किए गए निदेश के अनुपालन में और 'महापत्तनों' में प्रशुल्क के विनियमन हेतु दिशानिर्देश, 2004' के खंड 1.2 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण एतद्वारा संलग्न आदेशानुसार 31 मार्च 2005 को आदेश सं. टीएएमपी/23/2003-डब्ल्यूएस द्वारा अधिसूचित 'महापत्तनों' में प्रशुल्क के विनियमन हेतु दिशानिर्देश, 2004' की वैधता का और विस्तार करता है।

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

मामला सं. टीएएमपी/21/2009-डब्ल्यूएस

कोरम:

(i). श्री टी.एस. बालसुब्रमनियन, सदस्य (वित्त)

(ii). श्री रजत सचर, सदस्य (अर्थशास्त्र)

आदेश

(मार्च 2016 के 30वें दिन पारित)

महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 की धारा 111 के अधीन भारत सरकार द्वारा जारी किए गए नीति निर्देशों के अनुपालन में इस प्राधिकरण द्वारा राजपत्र सं. 39 द्वारा 31 मार्च 2005 को भारत के राजपत्र में 'महापत्तनों' में प्रशुल्क के विनियमन हेतु दिशानिर्देश, 2004' अधिसूचित किए गए थे। ये दिशानिर्देश 31 मार्च 2005 से लागू हुए थे और दिशानिर्देशों के खंड 1.2 में यथा विनिर्दिष्ट, 5 वर्षों की अवधि अर्थात् 31 मार्च 2010 तक के लिए प्रभावी रह गए थे, जब तक कि इस प्राधिकरण द्वारा पहले समीक्षा अथवा विस्तार नहीं किया गया हो।

2. महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 की धारा 111 द्वारा इस पर प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए "महापत्तन न्यासों हेतु प्रशुल्क के निर्धारण हेतु नीति, 2015" नामक महापत्तन न्यासों हेतु प्रशुल्क नीति पोत परिवहन मंत्रालय (एमओएस) द्वारा अपने पत्र सं. 8(1)/2014-टीएएमपी दिनांक 13 जनवरी 2015 द्वारा जारी की गई थी, और इस प्राधिकरण को तदनुसार तत्काल प्रभाव से कार्यान्वित करने का निदेश दिया गया था। तदनुसार, "महापत्तन न्यासों हेतु प्रशुल्क के निर्धारण के लिए नीति, 2015" नामक महापत्तन न्यासों हेतु प्रशुल्क नीति राजपत्र सं. 30 द्वारा 27 जनवरी 2015 को भारत का राजपत्र, असाधारण (भाग III खंड 4) में अधिसूचित की गई है। एमओएस द्वारा अपने पत्र दिनांक 13 जनवरी 2015 द्वारा यथा निर्देशित उक्त महापत्तन न्यासों हेतु प्रशुल्क नीति, 2015 को 13 जनवरी 2015 से लागू किया गया था। उक्त प्रशुल्क नीति, 2015 के

खंड 1.1. के अनुसार, यह महापत्तन न्यासों पर लागू है। प्रशुल्क नीति के खंड 1.3. में बताया गया है कि प्रशुल्क नीति, 2015 बीओटी/बीओओटी प्रचालकों अथवा निजी क्षेत्र भागीदारी हेतु किसी अन्य व्यवस्था पर लागू नहीं है।

3. जैसाकि एमओएस द्वारा सलाह दी गई है, इस प्राधिकरण ने 'महापत्तनों में प्रशुल्क के विनियमन हेतु दिशानिर्देश, 2004' की वैधता समय-समय पर विस्तारित की गई है। पिछले विस्तार में, एमओएस द्वारा अपने पत्र सं. पीआर-14019/20/2009-पीजी(पीटी-II) दिनांक 12 जून 2015 द्वारा दी गई सलाह अनुसार 1 अप्रैल 2015 से 31 मार्च 2016 तक अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, 2005 दिशानिर्देशों के अधीन वर्तमान में शासित महापत्तनों में प्रचालन कर रहे बीओटी टर्मिनल प्रचालकों हेतु प्राधिकरण द्वारा उक्त दिशानिर्देशों की वैधता का विस्तार किया गया था।

4. एमओएस ने अपने पत्र सं. पीआर-14019/20/2009-पीटी-III) दिनांक 21 मार्च 2016 द्वारा 'महापत्तनों में प्रशुल्क के विनियमन हेतु दिशानिर्देश, 2004' की वैधता 31 मार्च 2017 अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, विस्तारित किया गया है। इसके अलावा, एमओएस ने बताया है कि विस्तार केवल उन महापत्तन न्यासों में प्रचालन कर रहे बीओटी टर्मिनलों पर लागू की गई है जिनके प्रशुल्क का विनियमन उक्त 'महापत्तनों में प्रशुल्क के विनियमन हेतु दिशानिर्देश, 2004' द्वारा शासित किया जा रहा हो।

5. तदनुसार, महापत्तनों में प्रशुल्क के विनियमन हेतु दिशानिर्देश, 2004' की वैधता 31 मार्च 2017 अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, विस्तारित की गई है। यह विस्तार केवल उन महापत्तन न्यासों में प्रचालन कर रहे बीओटी टर्मिनलों पर लागू की गई है जिनके प्रशुल्क का विनियमन उक्त 'महापत्तनों में प्रशुल्क के विनियमन हेतु दिशानिर्देश, 2004' द्वारा शासित किया जा रहा हो।

टी. एस. बालसुब्रमनियन, सदस्य (वित्त)

[विज्ञापन- III/4/असा./143/16]

TARIFF AUTHORITY FOR MAJOR PORTS

NOTIFICATION

Mumbai, the 5th April, 2016

No.TAMP/21/2009-WS.—In compliance of the direction issued by the Government of India in Ministry of Shipping and in exercise of the powers conferred under clause 1.2 of the 'Guidelines for Regulation of Tariff at Major Ports, 2004', the Tariff Authority for Major Ports hereby further extends the validity of the 'Guidelines for Regulation of Tariff at Major Ports, 2004' notified vide Order No.TAMP/23/2003-WS on 31 March 2005, as in the Order appended hereto.

Tariff Authority for Major Ports

No. TAMP/21/2009 - WS

QUORUM

- (i). Shri. T.S. Balasubramanian, Member (Finance)
- (ii). Shri. Rajat Sachar, Member (Economic)

ORDER

(Passed on this 30th day of March 2016)

The 'Guidelines for Regulation of Tariff at Major Ports, 2004' were notified in the Gazette of India on 31 March 2005 vide Gazette No.39 by this Authority in compliance of policy directions issued by the Government of India under section 111 of the Major Port Trusts' Act, 1963. These guidelines came into effect from 31 March 2005 and as stipulated in clause 1.2 of the guidelines, remained in force for a period of 5 years, i.e. up to 31 March 2010, unless reviewed earlier or extended by this Authority.

2. The Ministry of Shipping (MOS) vide its letter No. 8(1)/2014-TAMP dated 13 January 2015 issued a Tariff Policy for Major Port Trusts called "Policy for Determination of Tariff for Major Port Trusts, 2015" in exercise of powers conferred on it by Section 111 of the Major Port Trusts Act, 1963, and directed the Authority to act accordingly with immediate effect. Accordingly, the Tariff Policy for Major Port Trusts called "Policy for Determination of Tariff for Major Port Trusts, 2015" has been notified in the Gazette of India Extraordinary (Part III Section 4) on 27 January 2015 vide Gazette No.30. The said Tariff Policy for Major Port Trusts, 2015 came into effect from 13 January 2015, as directed by the MOS vide its letter dated 13 January 2015. As per clause 1.1. of the said Tariff Policy 2015, it is applicable to Major Port Trusts. Clause 1.3. of the *ibid* Tariff Policy states that the Tariff Policy 2015 is not applicable to BOT/ BOOT operators or any other arrangement for Private Sector Participation.

3. As advised by the MOS, this Authority extended the validity of the 'Guidelines for Regulation of Tariff at Major Ports, 2004' from time to time. In the last extension, the validity of the said guidelines was extended by the Authority for BOT Terminal Operators operating at Major Ports presently governed under 2005 guidelines from 1 April 2015 to 31 March 2016 or until further orders, whichever is earlier, as advised by the MOS vide its letter No.PR-14019/20/2009-PG(pt-II) dated 12 June 2015.

4. The MOS vide its letter No.PR-14019/20/2009-PG(Pt.III) dated 21 March 2016 has extended the validity of "Guidelines for the Regulation of tariff at Major Ports, 2004" till 31 March 2017 or until further orders, whichever is earlier. Further, the MOS has stated that the extension is applicable only to the BOT terminals operating at the Major Port Trusts whose regulation of tariff is being governed by the said "Guidelines for Regulation of Tariff at Major Ports, 2004".

5. Accordingly, the validity of the 'Guidelines for Regulation of Tariff at Major Ports, 2004' is extended till 31 March 2017 or until further orders, whichever is earlier. This extension is applicable only to the BOT terminals operating at the Major Port Trusts whose regulation of tariff is being governed by the said "Guidelines for Regulation of Tariff at Major Ports, 2004".

T. S. BALASUBRAMANIAN, Member (Finance)

[ADVT.-III/4/Exty./143/16]